

योजना	शुभारंभ	द्वारा	प्रावधान
इन्द्रधनुष मिशन	16 Aug 2015	अरुण जैटली (वित्त मंत्री)	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की स्थिति सुधारने हेतु 7 सूची अभियान का आरंभ
मुद्रा बैंक योजना	8 Apr. 2015	नरेंद्र मोदी (प्रधानमंत्री)	इसमें बिजु, डिशोर तथा तरुण योजना के तहत क्रमशः 50000 से 10 लाख तक का गृहण दिया जाता है।
पहल योजना	1 Jan 2015.	उद्घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा	रस्तेई गैस के लिए ग्राहकों को प्रत्यक्ष नकद सब्सिडी दिए जाने की महत्वाकांक्षी योजना "पहल" विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना है।
प्रधानमंत्री जन-धन योजना	28 Aug 2014	शत प्रतिशत वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा	इस योजना के तहत स्वीकृत खातों के साथ जमा पर व्याज के अलावा रु० 1 लाख तक दुर्घटना बीमा कवर तथा 30000 रु० तक जीवन बीमा कवर की सुविधा उपलब्ध है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	1 May 2016 बलिआ (उ० प्र०)	नरेंद्र मोदी	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को अगले 3 वर्षों के भीतर 5 करोड़ मि: शुल्क दररू LPG सुविधा।
अटल पेंशन योजना	9 May 2015	प्रधानमंत्री द्वारा घोषित	→ 18-70 वर्ष की आयु के लोग शामिल। → सभी वचत बैंक खाता धारकों को रु० 12 वार्षिक प्रीमियम पर रु० 2 लाख का बीमा कवर (दुर्घटना के कारण मौत या अपंगता की स्थिति में)
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	9 May 2015 (कोलकाता से)	प्रधानमंत्री मोदी द्वारा	सभी बैंक खाता धारकों को वार्षिक रु० 330 के प्रीमियम पर रु० 2 लाख का बीमा कवर मिलेगा [18-40 वर्ष आयु]
सुकन्या समृद्धि योजना	22 Jan 2015 { बेटी-बचाओ बेटी-पढ़ाओ योजना के तहत }	नरेंद्र मोदी सरकार की पहल	इसके तहत कन्या के माता-पिता द्वारा उसकी 10 वर्ष की आयु तक बैंक में खाता खोलकर एक वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 1 हजार और अधिकतम 1.5 लाख जमा कराए जा सकते हैं। → यह राशि 14 वर्ष तक जमा करानी होगी तथा कन्या के 21 वर्ष की होने पर Mature होगी।
बेटी-बचाओ बेटी-पढ़ाओ योजना	22 Jan 2015 11 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में उम्र लिंगानुपात वाले 161 जिलों में से चयनित	प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा	→ इन सभी जिलों में जन्म के समय लिंगानुपात में 10% वृद्धि का लक्ष्य। → यह बालिकाओं की शिक्षा के लिए एक सामाजिक ओर्देलन और समान मूल्य को बढ़ावा देने का जागरूकता अभियान

धन राशि पर 9.1% प्रतिवर्ष व्याज दिया जाता है।

योजना	शुरुआत	द्वारा	प्रावधान
सुगम्य भारत अभियान	3 Dec 2015	मोदी सरकार	→ देश एवं राज्यों की राजधानियों की निःशक्त जनों के लिए अनुकूल बनाना। → निःशक्त जनों के लिए 1700 करोड़ की लागत से एक विश्व विद्यालय की स्थापना।
मिशन इन्डियन	5 Oct 2015 (द्वितीय चरण)	मोदी सरकार	2020 तक देश के 90% कच्चे को विभिन्न बीमारियों (काली खांसी, डिप्थीरिया, पोलियो, तपेदिक, खसरा, टिटनेस तथा टैपेटाइड्स-3) से सुरक्षित करने हेतु टीकाकरण।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना	23 Mar 2016 और स्वीकृति	केंद्रीय कैबिनेट द्वारा	→ दिल्ली एवं चंडीगढ़ को छोड़कर समूचे भारत में मैदानी क्षेत्रों में आवास निर्माण हेतु 1.20 लाख तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1.30 लाख की आर्थिक सहायता।
सबके लिए आवास योजना	29 Aug 2015 (9 राज्यों के 305 शहर शामिल)	केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना	इस योजना के तहत वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के लिए 2 करोड़ आवासों का निर्माण किया जाना तय है।
भारतम परियोजना	4 Apr. 2016 → (बजट → ₹ 102 अरब)	मोदी सरकार	देश के सभी राजमार्गों को वर्ष 2019 तक Railway Crossing मुक्त करना उद्देश्य।
श्रीमती प्रधानमंत्री रूरेन मिशन	21 Feb 2016	मोदी सरकार	इसके तहत स्मार्ट गाँव विकसित करना है। गाँवों के आर्थिक विकास, रोजगार वृद्धि, तथा ग्रामीण-शहरी अंतर कम करने के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं।
उद्यम योजना (उज्जवल डिस्कम रूरेन योजना (UDAY))	6 Nov 2015	मोदी सरकार	→ विद्युत वितरण कंपनियों के पुर्नर्गठन में सुधार हेतु निवारण उपाय। → वर्ष 2018-19 तक सभी विद्युत वितरण कंपनियों को लाभ में लाना लक्ष्य।
दीनदयाल उपा-ध्याय ग्राम ज्योति योजना	25 July 2015	राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के स्थान पर	इस योजना का उद्देश्य गाँवों में 24/7 विद्युत उपलब्ध कराना है। → 100% ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य है।
Smart City Mission	25 June 2015 (वर्ष 2015-20 के लिए 50000 करोड़ का उपबन्ध)	मोदी सरकार	→ इसके तहत चुने गए शहरों में आवास, स्वास्थ्य, संचार, परिवहन, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश कर अवसंरचनात्मक विकास किया जाएगा।
अमृत मिशन Atal Mission to Rejuvenation and Urban Transformation	AMRIT 25 June 2015.	मोदी सरकार	→ यह एक शहरी अवसंरचनात्मक मिशन है। → इसके तहत छोटे शहरों तथा कस्बों में आधारभूत सुविधाएँ विकसित की जाएंगी।

योजनाएँ	शुभारम्भ	द्वारा	प्रावधान
नमामि गंगे योजना →	14 May 2015	मोदी सरकार	→ आपक प्रयासों से गंगा नदी को स्वच्छ और संरक्षित किया जाना। → "राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण" के तहत संचालन।
हृदय योजना National Heritage City Development and Augmentation	21 Jan 2015	मोदी सरकार	→ इसका मुख्य उद्देश्य हेरिटेज (विरासत) शहरों को विकसित करना है। → शहरी विकास मंत्रालय द्वारा संचालन।
सांसद आदर्श ग्राम योजना	11 Oct 2014	मोदी सरकार	→ इसके तहत प्रत्येक सांसद को वर्ष 2019 तक 3 गाँवों को विकसित करना है। → इसका उद्देश्य भारत के गाँवों का भौतिक और संस्थागत ढाँचा को सम्पूर्ण विकास है।
स्वच्छ भारत मिशन	2 Oct 2014	प्रधानमंत्री मोदी द्वारा	→ यह निर्मल भारत कार्यक्रम का संशोधन है। → वर्ष 2019 (महात्मा गाँधी की 150वीं जयन्ती) तक भारत को स्वच्छ बनाना लक्ष्य।
डिजिटल इंडिया मिशन Note:- { इसके 3 दृष्टि हैं:- डिजिटल बुनियादी सेवाएँ, डिजिटल साक्षरता डिजिटल वितरण }	26 Aug 2014	मोदी सरकार	→ उद्देश्य भारत को डिजिटल आर्थिक व्यवस्था में बदलना। → इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सभी सरकारी सेवाओं को जनता तक पहुँचाना है।
नई मंजिल योजना	8 Aug 2015 (पटना से)	केंद्र सरकार	→ अल्पसंख्यकों के कल्याण, सशक्तिकरण और पुर्गति के संबंध में समग्र दृष्टिकोण अपनाने एवं उनकी स्थिति में सुधार देना।
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना	25 Sept 2014	मोदी सरकार	→ ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर। → 18-35 आयु वर्ग के युवा शामिल।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	15 July 2015	केंद्र सरकार	→ देशभर के 24 लाख युवाओं को विभिन्न उद्योगों से संबंधित प्रशिक्षण देना। → इसके तहत 10 करोड़ नए तथा 30 करोड़ वर्तमान भ्रम बल को कुशल बनाया जाएगा।
उस्ताद योजना { Upgrading the Skills and Training in Traditional Arts/Crafts for Development }	14 May 2014 (वाराणसी से)	मोदी सरकार	→ अल्पसंख्यकों की पारम्परिक कला/शिल्प की समृद्ध विरासत के संरक्षण और परंपरागत कारीगरों की क्षमता निर्माण देना।
राष्ट्रीय शैकुल मिशन	28 July 2014	मोदी सरकार	यह मिशन स्वदेशी गाँवों के संरक्षण से संबंधित है तथा पशु प्रजनन एवं उमरी विकास कार्यक्रम पर आधारित है।

योजना	शुभारम्भ	द्वारा	प्रावधान
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	19 Feb 2015 {हर खेत को पानी देना लक्ष्य}	मोदी सरकार	→ वर्ष में ऐसी अद्यतन ससम प्रणालियों का उपयोग करना जिससे जल अपव्यय कम हो। → आगामी 5 वर्षों में 50000 करोड़ व्यय।
मृदा स्वास्थ्य कर्डी योजना	19 Feb 2015 {मृदा गुणवत्ता परीक्षण}	मोदी सरकार	→ कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कर्डी जारी। → इस कर्डी पर मृदा की गुणवत्ता, अपेक्षित उर्वरक मात्रा प्रयोगशाला परीक्षण की रिपोर्ट्स पर दर्ज की जाएगी।
डिजिटल लोकर योजना (Digilocker)	7 Sept 2016	रविशंकर प्रसाद तथा नितिन गडकरी	→ इसके तहत सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों जैसे:- Driving License, PAN Card etc. को एक नि:शुल्क App में सुरक्षित रखा जाएगा (Soft Copy में)
उजाला योजना :-	11 Mar 2016 {विकासी दरों पर LED Bulbs उपलब्ध कराना लक्ष्य}	भारत सरकार	→ यह "उर्जा सहायता सेवा लि" द्वारा लागू किए जा रहे "सभी के लिए रियायती LED से उन्नत ज्योति" कार्यक्रम का संक्षिप्त नाम है।
स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना	14 Nov 2015 {पर्यटन स्थलों पर विश्व-स्तरीय सुविधा लक्ष्य}	मोदी सरकार	→ तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्द्धन अभियान पर राबड़ीय मिरान के तहत इन योजनाओं का संचालन।
स्वर्ण-भारत योजना	5 Nov 2015 {गोल्ड मैनोटाइजेशन, गोल्ड कोण्ड स्कीम तथा गोल्ड क्वार्टेन शामिल}	मोदी सरकार	→ सौने के आभास को नियंत्रित करना तथा घरेलू संग्रह की उपयोगिता बढ़ाना लक्ष्य।
मेरा जिला मेरी योजना	→ पूर्ण साक्षरता हासिल करने की दिशा में प्रौढ़ शिक्षा मिशन तथा जन जन शिक्षण संस्थानों में आधुनिक अनुसंधान एवं समय सीमा के भीतर साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। → उद्देश्य:- 40-60 वर्ष आयु वर्ग के निरक्षर लोगों को साक्षर बनाना।		
प्रधानमंत्री रक्षित क्षेत्र कल्याण योजना	17 Sept 2015	मोदी सरकार	रक्षित गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के लिए कार्य करना तथा उनके लिए रोजगार के अवसर सृजित करना लक्ष्य।
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम पंचायत योजना	17 Oct 2014 {उद्देश्य:- ग्राम क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करना तथा औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल योजनाएं तैयार करना}	मोदी सरकार	इसके तहत भ्रम निरीक्षण, एकीकृत भविष्यनिधि खाता नम्बर तथा भ्रम मंगालम में एकल खिड़की निष्पादन जैसी योजनाएँ शामिल हैं।

* स्टार्ट अप इंडिया (Start Up India) :-

- उद्देश्य:- नए शुरू किए जा रहे उद्यमों को बढ़ावा देना तथा उद्यमियों को प्रेरित करना।
- उल्लेख:- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा, 15 Aug 2015, लाल किला, नई दिल्ली।
- आरम्भ:- 16 Jan 2016, नई दिल्ली।
- प्रावधान:-
 - 1.) नए कारोबारों के लिए वित्त पोषण हेतु 10 हजार करोड़ का फंड
 - 2.) नए कारोबारों से अर्जित आय 3 वर्ष तक आकर से मुक्त तथा चैरिटेबल शुल्क में 80% की छूट।
 - 3.) मान्यता प्राप्त फंड्स में निवेश पर कैपिटल गेन टैक्स में छूट।
 - 4.) पहले 3 वर्षों तक श्रम एवं पर्यावरण संबंधी नियमों के पालन (9) के लिए उद्यमी स्वयं जिम्मेदार, सरकारी हस्तक्षेप नहीं।
 - 5.) सभी जानकारियाँ एवं मंजूरियाँ Online, Web portal तथा app (mobile) शुरू किया जाएगा।

9 नियम →

* स्टैंड अप इंडिया (Stand Up India)

- उद्देश्य:- दलितों, आदिवासियों एवं महिला उद्यमियों के लाभार्थ।
- उल्लेख:- 15 Aug 2015, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, लाल किला, नई दिल्ली।
- आरम्भ:- बाबू जगजीवन राम की जयंती (समता दिवस) 5 Apr. 2016.
- प्रावधान:-
 - 1.) देशी बैंकों की 1.25 लाख शाखाओं में प्रत्येक शाखा द्वारा कम से कम 2 परियोजनाओं के लिए लक्षित (दलित, आदिवासी, महिला उद्यमी) को प्रेरण उपलब्ध कराना।
 - 2.) प्रेरण राशी:- 10 लाख से 01 करोड़
 - 3.) अगले 3 वर्षों 2016-18 के बीच 2.5 लाख नए उद्यम।

* प्रधानमंत्री जन-धन योजना :-

- उद्देश्य:- देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना।
- उल्लेख:- 15 अगस्त, 2014, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा
- आरम्भ:- 28 अगस्त, 2014, नई दिल्ली [विशाल भवन]
- मुख्य बिंदु:-
 - 1.) देश भर में कुल मिलाकर 1.50 करोड़ बैंक खाते पहले दिन।
 - 2.) प्रधानमंत्री ने बैलिक फोन पर Mobile Banking की शुरुआत की।
 - 3.) जन-धन योजनाओं का लक्ष्य बैंकिंग सेवाओं की पहुँच से दूर 7.5 करोड़ परिवारों को बैंक खातों की सुविधा उपलब्ध कराना था तथा यह लक्ष्य 26 जून 2015 तक प्राप्त कर लिया गया।
 - 4.) 28 Aug 2015 को योजना के एक वर्ष पूर्ण होने तक कुल 17.5 करोड़ बैंक खाते इस योजना के तहत खोले गए थे तथा कुल जमा राशी 22,000 करोड़ से अधिक थी।
 - 5.) योजना के तहत बैंक खाताधारकों को स्वदेशी रुपये (Ru Pay) डेबिट कार्ड तथा 1 लाख की दुर्घटना बीमा सुरक्षा प्रदान।
 - 6.) 26 जून 2015 से पूर्व खाता खोलने वालों को 30 हजार का बीमा कवच उपलब्ध कराया गया।
 - 7.) खाता खुलाने के 6 माह के पश्चात ₹ 2500 की overdraft सुविधा आधार संबंधित खाते में उपलब्ध कराई गई जिसने 6 माह के पश्चात 5000 तक बढ़ा दिया गया।

Chandra Vardham

* मेक इन इंडिया (Make In India) कार्यक्रम :-

Chandra Vasudhan

(2)

- उद्देश्य :- निवेश को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास की गति को तेज करना तथा देश को Manufacturing Hub बनाना।
- शुरुआत :- 25 Sept 2014 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, विधान भवन, नई दिल्ली।
- प्रतीक चिह्न :- शेर (अशोक चक्र का डिस्का तथा साहस, हृदयमत्ता, शक्ति का प्रतीक)
- मुख्य बिन्दु :-
 - 1) FDI को First Develop India के रूप में परिभाषित किया।
 - 2) देश के पास उपस्थित 3-D (Demography, Democracy & Demand) शक्ति का उल्लेख साथ ही देश की Look East Policy के साथ Link West का मंत्र प्रधानमंत्री ने दिया।
 - 3) Reliance Industries के Chairman मुकेश अंबानी ने विभिन्न क्षेत्रों में 1,80,000 करोड़ के निवेश की बात Launching पर की।

* स्किल इंडिया मिशन (Skill India Mission) :-

- उद्देश्य :- देश की युवा मानव शक्ति को वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए कौशल एवं योग्यता उपलब्ध कराना।
- शुरुआत :- 15 July 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा, नई दिल्ली।
- मुख्य बिन्दु :-
 - 1) नई कौशल विकास तथा उद्यमिता नीति की घोषणा
 - 2) देश में केवल 2.3% कार्यबल (Work Force) को ही अपने कार्य के संबंध में औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त है जबकि जर्मनी में 75%, अमरीका में 52%, जापान में 80% तथा दक्षिण कोरिया - 96%।
 - 3) कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की पहल पर National Mission For Skill Development (NMSD) की शुरुआत।
 - 4) 2022 तक 30 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य।
 - 5) प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक Governing Council, Steering Committee एवं एक मिशन निदेशालय की स्थापना का प्रावधान।

* उद्यम योजना (Ujjwal DISCOM Assurance Yojana, UDAY) :-

- उद्देश्य :- विद्युत वितरण कंपनियों (Distribution Companies, DISCOMs) की वित्तीय स्थिति में सुधार तथा उनका पुनरुत्थान।
- मंजूरी :- विद्युत मंत्रालय की इस योजना (UDAY) को केंद्रीय मंत्रीमंडल ने 5 Nov 2015 को मंजूरी दी।
- प्रावधान :- "उद्यम" योजना के तहत DISCOMs को अगले 2 से 3 वर्षों में घाटे तथा कर्ज (घाटा - 3.8 लाख करोड़, कर्ज - 4.3 लाख करोड़) से उबारने के लिए 4 पहल :-
 - 1) DISCOMs की संचालनगत कुशलताओं को बेहतर बनाना।
 - 2) विद्युत की लागत में कमी लाना।
 - 3) DISCOMs की व्याज लागत में कमी।
 - 4) राज्य वित्तों के साथ समन्वय के लिए जरूरत DISCOMs पर वित्तीय अनुशासन योजना।

Note :- राज्यों के DISCOM कंपनियों के 75% ग्रहण का (30 Sept 2015 की स्थिति के अनुसार) take over राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा [50% 2015-16 में तथा 25% 2016-17 में]। इस ग्रहण की गणना राज्यों के राजकीय वित्तों की गणना में शामिल नहीं की जाएगी।

* प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना :-

- उद्देश्य:- विभिन्न आपदाओं से कृषिगत उत्पादन में होने वाले नुकसान की बेहतर एवं सुगम भरपूर।
- शुरुआत:- 13 जून 2016 को मंजूरी, स्वरीफ-2016 से लागू।
- मुख्य बिन्दु:- स्वरीफ की सभी उपजों के लिए बीमित राशी का 2.0% तथा रबी उपजों के लिए 1.5% किसानों द्वारा भुगतान [Premium]
- वार्षिक, वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिए किसानों द्वारा दत्त Premium बीमित राशी का 5.0% (शेष सरकार द्वारा)
- Post harvest (कटाई के बाद) नुकसान भी शामिल।
- One Nation One Scheme (एक राष्ट्र-एक योजना) के थीम (Theme) पर तैयार की गई योजना।

* प्रधानमंत्री मुद्रा योजना :-

- उद्देश्य:- वित्त पोषण की सुविधा से वंचित छोटे व्यवसायियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।
- उल्लेख:- वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा 2015-16 का बजट पेश करते हुए।
- आरम्भ:- 8 Apr. 2015, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, विमान भवन, नई दिल्ली।
- मुख्य बिन्दु:- छोटे उद्यमियों को उनके कारोबार में मदद के उद्देश्य से "सिडबी" (SIDBI - Small Industries Development Bank Of India) की अनुषंगी इकाई के रूप में मुद्रा लि. की स्थापना (MUDRA:- Micro Units Development Refinance Agency) एक बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC: Non Banking Financial Company) के रूप में March, 2015 में की गई थी।
- इस संस्था का मुख्य उद्देश्य Micro, लघु तथा मध्यम उपक्रमों को ऋण उपलब्ध कराने वाली Micro Finance संस्थाओं को गृहण उपलब्ध कराना है।
- मुद्रा लि. को अब SIDBI के ही अधीन एक बैंक (मुद्रा सिडबी बैंक) के रूप में रूपांतरित किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अन्तर्गत 8 Apr 2015 के पश्चात स्वीकृत गृहों के लिए ₹ 3000 करोड़ के Credit Guarantee fund का अनुमोदन।
- RBI के पास पंजीकृत सभी Micro Finance Institutions के निधामक या ~~दायित्व~~ दायित्व RBI के पास रहेगा।
- मुद्रा गृहों की श्रेणियाँ :-
 - 1) शिशु गृह :- 50-50 हजार तक
 - 2) किशोर गृह :- 50 हजार से 5 लाख तक
 - 3) तरुण गृह :- 5 लाख से 10 लाख तक

Note :- इस योजना का मुख्य उद्देश्य To Fund The Unfunded होगा।

* ग्रामीण से भारत उद्यम अभियान :- (14-24 Apr 2016)

→ लक्ष्य :- देश के समस्त गाँवों में पंचायती राज व्यवस्था सुदृढ़ कर सामाजिक सहभाव बढ़ाने, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने तथा किसानों की पुर्गति व गरीबों की जीविका के लिए राष्ट्रव्यापी प्रयास करना।

→ मुख्य विन्दु :- 14 Apr. 2016 को डॉ० भीमराव अंबेडकर की 125 वीं जयंती पर अभियान का शुभारंभ [म.प्र. के मऊ जिले के एक ग्राम से]
→ 24 Apr. 2016 को पंचायती राज दिवस पर समापन।
→ समापन पर प्रधानमंत्री का जमशेदपुर से संबोधन।

* सांसद आदर्श ग्राम योजना :- (SAGY)

→ उद्देश्य :- गाँवों के समग्र विकास के लिए हर सांसद द्वारा 2016 तक 1-1 तथा 2019 तक 3-3 गाँवों में संस्थागत तथा बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराना।

→ घोषणा :- 15 Aug 2014 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, लाल छिला से।

→ आरम्भ :- 11 Oct 2014 को लोकनाथ जमपुकाश नारायण की जयंती के अवसर पर।

Note :- इस योजना के लिए सांसदों द्वारा मौजूदा योजनाओं के तहत उपलब्ध कोषों व स्वयं की 5.5 करोड़ की सांसद निधि का इस्तेमाल किया जाएगा।

→ सांसद को कोई भी गाँव चुनने की आजादी (उसका/उसकी संसुराल नहीं)

* → प्रत्येक सांसद द्वारा 1 गाँव का विकास 2016 तक, March 2019 तक 3 तथा 2024 तक 5 आदर्श ग्रामों का विकास।

→ कुल 661 सांसदों ने Feb. 2015 के अंत तक विभिन्न गाँवों में विकास के लिए जिनमें लोकसभा के 485 तथा राज्य सभा के 176 सांसद शामिल।

→ प्रधानमंत्री द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के जथापुर गाँव का चयन।

→ अन्य प्रमुख नेताओं द्वारा चयनित गाँव :-

* राजनाथ सिंह - लावनऊ के पास "बैली" गाँव।

* राध मंत्री हरिभई चौधरी - पंथवाड़ा गाँव, गुजरात।

* नजमा टैपतुल्ला - भीपाल का "फोदा" गाँव।

* नितिन गडकरी - "पंचगाँव" गाँव, नागपुर।

* सचिन तेंदुलकर - पुद्दमरायू कंडेगा गाँव, आन्ध्र प्र०।

* मुलाग्रम सिंह यादव - उजाग्रगढ़ का "तुमली" गाँव।

* सुश्री माधवती - मलीहाबाद (उ० प्र०) का "मालगाँव"।

* सोनिया गाँधी - "उदवा" गाँव, जगतपुर ब्लॉक, रामबरेली।

* राहुल गाँधी - "दीह" गाँव, " " " " " "

Chander Jadhav